Vishv UMIYA Foundation | VUF INSTITUTE CIVIL SERVICES

DAILY CURRENT AFFAIRS

IN HINDI

SPECIAL FOR UPSC & GPSC EXAMINATION

DATE : 17-06-25

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Tuesday, 17 June, 2025

Edition : International Table of Contents

Page 01 **Syllabus : GS 3 : Indian Economy**	कुल निर्यात में वृद्धि के कारण भारत का कुल व्यापार घाटा घटकर 6.6 बिलियन डॉलर रह गया
Page 05 **Syllabus : GS 2 : International Relations**	मोदी जी7 आउटरीच शिखर सम्मेलन के लिए कनाडा पहुंचेंगे, द्विपक्षीय बैठकें करेंगे
Page 05 **Syllabus : GS 2 : International Relations**	एफएटीएफ ने पहलगाम हमले की निंदा की, 'राज्य प्रायोजित आतंकवाद' पर रिपोर्ट जारी करेगा
Page 10 **Syllabus : GS 1 : Culture & Geography**	शिपकी ला दर्रे का क्या महत्व है?
Page 11 **Syllabus : GS 3 : Science and Technology**	भारत के परमाणु दायित्व कानून में क्या अस्पष्टताएं हैं?
Page 08 : Editorial Analysis: **Syllabus : GS 2 : International Relations**	बंगाल की खाड़ी में भारत का असहज संतुलन

Page 01 : GS 3 : Indian Economy

भारत का कुल व्यापार घाटा मई 2025 में घटकर 6.6 अरब डॉलर रह गया, जो बाह्य व्यापार स्थिति में सुधार को दर्शाता है। यह सुधार मुख्यतः सेवाओं के निर्यात में वृद्धि और तेल आयात में गिरावट के कारण हुआ है। यह विकास भारत के सेवा क्षेत्र की मजबूती और वैश्विक ऊर्जा कीमतों की अस्थिरता का देश के व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव को उजागर करता है।

India's total trade deficit narrows to $6.6 billion as total exports grow

T.C.A. Sharad Raghavan
NEW DELHI

India's overall trade deficit narrowed to $6.6 billion in May 2025, down nearly 30% from its level in May last year, as total imports fell largely due to a fall in oil prices while total exports grew on the back of a strong performance by the services sector, official data show.

According to the monthly data released by the Ministry of Commerce and Industry on Monday, total exports grew 2.8% to $71.1 billion in May 2025 – up from $69.2 billion in May 2024 – with exports in the service sector growing 9.4% to $32.4 billion. Merchandise exports, on the other hand, contracted 2.2% to $38.7 billion, while non-petroleum exports reported a 5.1% growth.

The data shows that India's non-petroleum exports grew 5.1% in May 2025.

Merchandise imports too were impacted by falling oil prices. While total merchandise imports contracted 1.7% in May 2025, the non-petroleum imports grew 10% in the same month. Services imports grew 1.5%. Taken together, total imports contracted 1% in May 2025.

According to Commerce Secretary Sunil Barthwal, a large part of the reason for the subdued performance in merchandise exports is the fall in global oil prices.

"For May, there is positive growth in non-petroleum exports because petroleum, in times of crisis, there is a lot of volatility," Mr. Barthwal said at a briefing on the trade data. "Currently, there is new volatility that has come. And we have also seen, in the last two months, there was a sustained fall in prices in petroleum, which has got a dampening impact on exports."

Total exports grew 2.8% to $71.1 billion in May 2025 – up from $69.2 billion in May 2024

Dip in deficit

Strong showing by service exports, which grew by 9.4% to $32.4 billion in May 2025, boosted overall exports

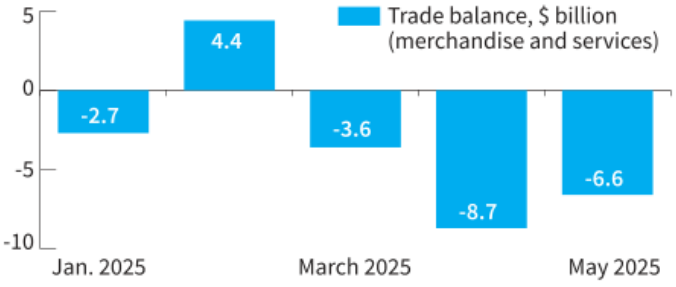

SOURCE: MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

आँकड़ों में प्रमुख प्रवृत्तियाँ:

• सेवाक्षेत्र अग्रणी भूमिका में

- **सेवाओं का निर्यात 9.4% बढ़कर 32.4 अरब डॉलर तक पहुंच गया**, जो भारत की IT, बीपीओ और डिजिटल सेवाओं की ताकत को दर्शाता है।
- मजबूत सेवाक्षेत्र ने माल व्यापार में कमजोरी की भरपाई की।

• माल निर्यात पर दबाव

- कुल **माल निर्यात 2.2% घटकर 38.7 अरब डॉलर रहा**।
- **गैर-पेट्रोलियम माल निर्यात में 5.1% की वृद्धि** दर्ज की गई, जिससे इंजीनियरिंग उत्पादों, फार्मास्युटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की मांग का संकेत मिलता है।
- पेट्रोलियम निर्यात में गिरावट का कारण वैश्विक तेल कीमतों में कमी और बाज़ार की अस्थिरता रही।

• आयात की प्रवृत्तियाँ और तेल कीमतों का प्रभाव

- कुल माल आयात में **1.7% की गिरावट** आई, जो मुख्यतः तेल आयात में गिरावट के कारण है।
- **गैर-पेट्रोलियम आयात में 10% की वृद्धि** दर्ज की गई, जिससे पूंजी और उपभोक्ता वस्तुओं की मजबूत घरेलू मांग का संकेत मिलता है।
- **सेवा आयात में 1.5% की मामूली वृद्धि** हुई, जिससे कुल आयात वृद्धि -1% पर सीमित रही।

विश्लेषण और प्रभाव:

• तेल कीमतों के प्रति संवेदनशीलता:

- भारत का व्यापार संतुलन वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बना हुआ है, क्योंकि तेल आयात का बड़ा हिस्सा है और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों के रूप में निर्यात भी होता है। कीमतों में गिरावट से आयात बिल तो घटता है, लेकिन निर्यात आय पर भी असर पड़ता है।

• सेवाक्षेत्र में संरचनात्मक मजबूती:

- सेवा क्षेत्र व्यापार घाटे को संतुलित करने के लिए एक स्थिर विदेशी मुद्रा स्रोत बना हुआ है। यह भारत की बाह्य क्षेत्र की एक रणनीतिक ताकत है, जिसे नीति प्रोत्साहनों के माध्यम से और सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

• व्यापार विविधीकरण की आवश्यकता:

- माल निर्यात में गिरावट यह दर्शाती है कि **निर्यात टोकरी का विविधीकरण** और **नए बाज़ारों में प्रवेश** बेहद जरूरी है, खासकर ऐसे समय में जब वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव और मांग में मंदी जैसी अनिश्चितताएँ बनी हुई हैं।

• अल्पकालिक राहत, दीर्घकालिक सतर्कता:

- व्यापार घाटे में कमी एक सकारात्मक संकेत है जो **मैक्रोइकोनॉमिक स्थिरता** की ओर इशारा करता है, लेकिन भारत को बाहरी झटकों, विशेष रूप से **ऊर्जा सुरक्षा** और तेल उत्पादक क्षेत्रों में **भू-राजनीतिक तनावों** के प्रति सतर्क रहना होगा।

निष्कर्ष:

मई 2025 में भारत का घटा हुआ व्यापार घाटा तेल कीमतों में कमी और सेवाओं के मजबूत निर्यात का अनुकूल परिणाम है, लेकिन आँकड़े यह भी इंगित करते हैं कि माल व्यापार में अधिक लचीलापन लाने की आवश्यकता है। **गैर-तेल निर्यात** को बढ़ाने,

सेवाओं की प्रतिस्पर्धात्मकता को सशक्त करने, और **ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं** को सुरक्षित करने के लिए रणनीतिक योजना आवश्यक है, ताकि दीर्घकालिक व्यापार स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।

UPSC Mains Practice Question

Ques : मई 2025 में भारत का व्यापार घाटा कम हो गया, जिसमें मजबूत सेवा निर्यात और तेल की गिरती कीमतों ने मदद की। भारत की बाहरी क्षेत्र स्थिरता और दीर्घकालिक व्यापार नीति के लिए इन प्रवृत्तियों के निहितार्थों पर चर्चा करें। **(250 words)**

Page 05 : GS 2 : Internaional Relations

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कनाडा के कैलगरी में आयोजित G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में भागीदारी भारत की विकसित होती बहुपक्षीय कूटनीति का एक महत्वपूर्ण क्षण है। यह मई 2025 में चलाए गए **ऑपरेशन सिंदूर**, भारत के लक्षित आतंकवाद विरोधी अभियान के बाद उनकी पहली बड़ी बहुपक्षीय भागीदारी है, और यह ऐसे समय में हो रही है जब वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव, विशेषकर **इज़राइल-ईरान** और **रूस-यूक्रेन** संघर्ष, अपने चरम पर हैं।

Modi to reach Canada for G7 Outreach Summit, will hold bilateral meets

This is his first multilateral event after the conclusion of Operation Sindoor; the summit is being watched keenly as it is being held against the backdrop of Israel-Iran and Russia-Ukraine conflicts

Kallol Bhattacherjee
NEW DELHI

Prime Minister Narendra Modi departs from Cyprus to attend the G7 Outreach Summit in Canada. ANI

Prime Minister Narendra Modi is scheduled to reach Calgary, Canada on Monday to attend the G7 Outreach Summit.

The summit is being watched keenly as it is being held against the backdrop of escalating Israel-Iran and Russia-Ukraine conflicts.

Apart from Mr. Modi, Ukraine President Volodymyr Zelenskyy will be among the guests in the summit that will be held in Kananaskis, Alberta.

The Group of Seven (G7) is an informal grouping of the world's advanced economies. It is made up of seven member countries – France, the U.S., the U.K., Germany, Japan, Italy, and Canada – and the European Union.

Mr. Modi's visit to Canada, taking place after a brief visit to Cyprus, is being viewed with interest here as it will give an opportunity to him and the new Canadian Prime Minister Mark Carney to warm up India-Canada ties that had nosedived during the Premiership of Justin Trudeau after he alleged in September 2023 that Indian state actors were behind the June 18, 2023 murder of pro-Khalistan activist Hardeep Singh Nijjar. Earlier, Mr. Carney had taken a step forward to normalisation of ties by highlighting India's global profile that he said required engagement.

"At the summit, the Prime Minister will exchange views with leaders of G7 countries, other invited outreach countries and Heads of International Organisations on crucial global issues, including energy security, technology and innovation, particularly the AI-energy nexus and Quantum-related issues," the External Affairs Ministry had said in New Delhi. The G7 summit is the first multilateral event that Mr. Modi will attend after the conclusion of Operation Sindoor against terror targets in Pakistan in May. Apart from Prime Minister Carney, Mr. Modi is expected to meet multiple other leaders of the G7 and the guest countries.

Three core issues

The G-7 Outreach Summit is scheduled for Tuesday noon which will be themed around three core issues of "Protecting our communities around the world", "Building energy security and accelerating the digital transition" and "securing the partnerships of the future". Apart from Mr. Modi, and Mr. Zelenskyy, host Canada has invited leaders of Australia, Brazil, Mexico, South Africa, and South Korea.

Following his engagements in Canada, Mr. Modi will leave on Tuesday evening for Zagreb, Croatia which is last of his three-nation tour.

(With PTI inputs)

G7 आउटरीच: भारत के लिए इसका महत्व

• रणनीतिक संवाद का मंच:

- यद्यपि भारत G7 का सदस्य नहीं है, फिर भी आउटरीच सत्रों में उसकी निरंतर उपस्थिति यह दर्शाती है कि **वैश्विक निर्णय-निर्माण में उसकी बढ़ती भूमिका** और **विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए उसकी रणनीतिक उपयोगिता** कितनी महत्वपूर्ण है।

• ऑपरेशन सिंदूर के बाद की कूटनीति:

- यह **ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी की पहली बहुपक्षीय उपस्थिति** है। यह सम्मेलन भारत की **आतंकवाद विरोधी रणनीति** को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने और प्रमुख वैश्विक शक्तियों से समर्थन या तटस्थता हासिल करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।

• भारत-कनाडा संबंधों में पुनर्स्थापन:

- यह यात्रा अतिरिक्त महत्व रखती है क्योंकि मोदी **नए कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी** से मिलने वाले हैं। यह मुलाकात पूर्व पीएम **जस्टिन ट्रूडो द्वारा निज्जर हत्या मामले** में लगाए गए आरोपों के बाद तनावपूर्ण संबंधों को **सुधारने का अवसर** बन सकती है। कार्नी के हालिया भारत-समर्थक बयानों ने **सुलह का राजनयिक मार्ग** खोला है।

मुख्य विषयवस्तु और भारत के हित

• ऊर्जा सुरक्षा और डिजिटल संक्रमण:

- भारत **संतुलित ऊर्जा नीति** की वकालत करेगा, जिसमें **स्वच्छ ऊर्जा, वहनीयता और न्यायसंगत संक्रमण** पर बल दिया जाएगा, साथ ही **डिजिटल समावेशन, AI नियमन और क्वांटम इनोवेशन** को ग्लोबल साउथ के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया जाएगा।

• वैश्विक सुरक्षा और आतंकवाद-विरोध:

- इज़राइल-ईरान और रूस-यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में भारत **संप्रभुता के सम्मान, रणनीतिक संयम और सीमा पार आतंकवाद के लिए शून्य सहिष्णुता** की अपनी नीति दोहराएगा।

• भविष्य की साझेदारियाँ:

- भारत G7 सदस्यों और ब्राज़ील, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका जैसे अतिथि देशों के साथ संबंधों को मज़बूत करने का प्रयास करेगा — **ग्लोबल साउथ की एकता, डिजिटल सहयोग और आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण** को बढ़ावा देते हुए।

व्यापक प्रभाव

• बहुपक्षीय प्रभाव को सशक्त बनाना:

- G7 आउटरीच में भारत की निरंतर भागीदारी यह दर्शाती है कि वह **विकसित और विकासशील विश्वों के बीच एक सेतु** के रूप में उभर रहा है और बहुपक्षीय मंचों में **ग्लोबल साउथ की आवाज़** बन रहा है।

• ऑपरेशन सिंदूर के बाद नैरेटिव नियंत्रण:

- एक विवादास्पद सैन्य अभियान के तुरंत बाद उच्चस्तरीय सम्मेलन में भाग लेकर भारत वैश्विक मंच पर **अपना पक्ष रखने, शक्ति प्रक्षेपित करने और सुरक्षा चिंताओं के लिए वैधता** प्राप्त करने की रणनीति अपनाता दिख रहा है।

• द्विपक्षीय कूटनीति के अवसर:

- यह सम्मेलन G7 नेताओं के साथ कई **द्विपक्षीय बैठकों** के लिए मंच प्रदान करता है — जिनमें अमेरिका, फ्रांस और EU के साथ **रक्षा सहयोग, प्रौद्योगिकी साझेदारी और इंडो-पैसिफिक रणनीति** पर चर्चा संभावित है।

निष्कर्ष:

2025 का G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन केवल एक कूटनीतिक आयोजन नहीं, बल्कि एक **रणनीतिक मंच** है जहाँ भारत **राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को संतुलित करने, तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने**, और विशेष रूप से **कनाडा के साथ तनावपूर्ण संबंधों को पुनर्जीवित** करने का प्रयास करेगा। जैसे-जैसे वैश्विक भू-राजनीति अधिक खंडित होती जा रही है, ऐसे मंचों पर भारत की सक्रिय भागीदारी **नई शक्ति समीकरणों के निर्माण, अपने संप्रभु हितों की रक्षा** और **एक जिम्मेदार वैश्विक अभिनेता** के रूप में अपनी भूमिका सुदृढ़ करने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

UPSC Mains Practice Question

Ques: जी7 आउटरीच शिखर सम्मेलन जैसे वैश्विक समूहों में भारत की भागीदारी इसकी बढ़ती कूटनीतिक छवि को दर्शाती है। वर्तमान वैश्विक संदर्भ में भारत के लिए ऐसी सहभागिताओं के रणनीतिक महत्व पर चर्चा करें। **(250 words)**

Page : 05 : GS 2 : Internaional Relations

आर्थिक कार्रवाई कार्यबल (FATF) — जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के लिए समर्पित विश्व की प्रमुख अंतर-सरकारी संस्था है — ने **22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की एक दुर्लभ और तीव्र निंदा** की है। महत्वपूर्ण रूप से, FATF पहली बार एक ऐसी रिपोर्ट जारी करने जा रही है जिसमें **राज्य प्रायोजित आतंकवाद को आतंक वित्तपोषण के एक विशिष्ट स्रोत** के रूप में पहचाना जाएगा — यह कदम भारत की लंबे समय से उठाई जा रही इस चिंता के लिए अत्यंत प्रासंगिक है कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देता है।

इसका महत्व क्यों है:

- **FATF की दुर्लभ निंदा:**
  - यह एक दशक में केवल तीसरी बार है जब FATF ने किसी आतंकवादी हमले की सार्वजनिक रूप से निंदा की है — यह दर्शाता है कि **पहलगाम घटना की गंभीरता और उस पर अंतरराष्ट्रीय चिंता** कितनी गहरी है।
- **राज्य-प्रायोजित आतंकवाद पर ध्यान केंद्रित:**
  - आने वाली FATF रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से **राज्य-समर्थित संस्थाओं को आतंक के वित्तपोषक** के रूप में पहचाने जाने की उम्मीद है। यह भारत के उन लगातार दावों को वैधता देता है कि **पाकिस्तान ने अपनी ज़मीन से काम कर रहे आतंकवादी समूहों को समर्थन और आश्रय दिया है।**
- **FATF दृष्टिकोण में नीति परिवर्तन:**
  - अब तक मुख्य रूप से गैर-राज्य तत्वों और अवैध वित्तीय नेटवर्कों पर केंद्रित रही FATF अब **राज्य की संलिप्तता को ध्यान में रख रही है**, जो वैश्विक आतंक वित्तपोषण को समझने और विनियमित करने के तौर-तरीकों में **एक व्यापक बदलाव** का संकेत है।

FATF condemns Pahalgam attack, to release report on 'state-sponsored terror'

T.C.A. Sharad Raghavan
NEW DELHI

The Financial Action Task Force (FATF), the apex inter-governmental anti-terror financing watchdog, has issued a statement condemning the Pahalgam terror attack, noting that it "could not occur without money and the means to move funds between terrorist supporters".

According to sources, this is a significant condemnation as it is only the third time in the last decade that a terror attack has been condemned by the FATF. Further, it is learnt that the FATF will release a report next month which, for the first time, will include state-sponsorship as a separate source of funding of terror.

The Hindu had reported earlier about how the government was sending a dossier to the FATF to argue in favour of including Pakistan in the 'grey list' of countries that warranted greater scrutiny.

"Terrorist attacks kill, maim, and inspire fear around the world," the FATF said in a statement. "The FATF notes with grave concern and condemns the brutal terrorist attack in Pahalgam on 22 April 2025. This, and other recent attacks, could not occur without money and the means to move funds between terrorist supporters."

People in Guwahati protesting against the terrorist attack in Pahalgam, on April 23. RITU RAJ KONWAR

According to sources aware of these developments, the FATF "rarely" issues a condemnation of terrorist acts.

Third in a decade

"It is only the third time in the last decade that they have issued a condemnation of a terrorist attack," the source said. "It has issued the condemnation because the international community has felt the severity of the attack and highlights that such attacks will not go unpunished."

According to the sources, the FATF has also developed a Terror Financing Risk & Context toolkit for assessors, so that countries such as Pakistan cannot "fool them with lies" about the terror financing risks from their jurisdictions.

The FATF will soon release a comprehensive analysis of terrorist financing and will host a webinar to help the public and private sectors understand the risks and stay alert to emerging threats. Sources said this report would be out in a month.

"The FATF is releasing a report on terror financing risks in a month's time," the source said. "This is the first time the concept of 'state-sponsored terrorism' is being acknowledged by FATF as a funding source. Only India's National Risk Assessment recognises state-sponsored terrorism from Pakistan as a key terror financing risk."

• भारत के लिए रणनीतिक लाभ:

- भारत, जिसने पाकिस्तान के वित्तीय नेटवर्कों की गहन जांच की मांग करते हुए डोज़ियर प्रस्तुत किए थे, अब **FATF की 'ग्रे लिस्ट' में पाकिस्तान को दोबारा शामिल करने के लिए दबाव** बनाने की बेहतर स्थिति में है — जो इस्लामाबाद को आर्थिक और राजनयिक रूप से प्रतिबंधित कर सकता है।

• FATF का वैश्विक टूलकिट विस्तार:

- नया **Terror Financing Risk & Context Toolkit** FATF के मूल्यांकनकर्ताओं को क्षेत्रीय स्तर पर जोखिम को बेहतर ढंग से पहचानने की सुविधा देगा, जिससे पाकिस्तान जैसे देशों द्वारा मूल्यांकन के समय भटकाव या गुमराह करने की संभावना कम होगी।

भारत के लिए प्रभाव:

• आतंकवाद विरोधी कूटनीति को बढ़ावा:

- भारत FATF की इस नई सोच का लाभ उठाकर उन देशों के विरुद्ध **वैश्विक सहमति** बनाने का प्रयास कर सकता है जो आतंकवादी संगठनों को **वित्तीय या भौतिक समर्थन** प्रदान करते हैं।

• भारत के नैरेटिव को वैधता:

- **राज्य-प्रायोजित आतंकवाद की वैश्विक नियामक ढांचे में मान्यता** भारत के सुरक्षा दृष्टिकोण को संयुक्त राष्ट्र और G20 जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अधिक वैधता देती है।

• घरेलू जोखिम मूल्यांकन को सुदृढ़ करना:

- भारत का **राष्ट्रीय जोखिम मूल्यांकन (NRA)** पहले से ही पाकिस्तान-प्रायोजित आतंकवाद को प्रमुख वित्तपोषण खतरे के रूप में मान्यता देता है। अब FATF के साथ यह तालमेल भारत की **घरेलू खुफिया और वित्तीय निगरानी प्रणाली** की विश्वसनीयता को और मजबूत करता है।

• भारत-पाक संबंधों पर प्रभाव:

- यह घटनाक्रम **द्विपक्षीय संबंधों को और तनावपूर्ण बना सकता है** और पाकिस्तान पर अपने आतंकी नेटवर्कों को नियंत्रित करने का अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ा सकता है — विशेष रूप से FATF की किसी आगामी समीक्षा से पहले।

निष्कर्ष:

FATF द्वारा पहलगाम आतंकी हमले की दुर्लभ और सशक्त निंदा तथा **राज्य-प्रायोजित आतंकवाद पर केंद्रित रिपोर्ट** का प्रस्ताव वैश्विक आतंक वित्तपोषण विमर्श में **एक ऐतिहासिक बदलाव** का संकेत देता है। भारत के लिए यह एक **रणनीतिक विजय** है, जो आतंकवाद के विरुद्ध उसके नैतिक और कूटनीतिक अधिकार को मजबूत बनाती है और **सुरक्षा तथा वित्तीय खुफिया जानकारी पर अंतरराष्ट्रीय समन्वय** को बढ़ावा देती है।

UPSC Mains Practice Question

Ques: वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के संदर्भ में राज्य प्रायोजित आतंकवाद पर इसके बदलते रुख के महत्व पर चर्चा करें। ***(250 Words)***

Page 10 : GS 1 : Culture & Geography

हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित शिपकी ला दर्रा, जो कभी भारत और तिब्बत के बीच एक समृद्ध व्यापारिक गलियारा हुआ करता था, को पहली बार **बिना परमिट के घरेलू पर्यटन** के लिए खोल दिया गया है। यद्यपि व्यापार अभी भी निलंबित है, इस कदम ने **सांस्कृतिक आदान-प्रदान, आर्थिक पुनर्जीवन और धार्मिक पर्यटन** की संभावनाओं को पुनर्जीवित किया है, जिनके दूरगामी **रणनीतिक और राजनयिक प्रभाव** हो सकते हैं।

What is the significance of the Shipki La pass?

Why was tourism and trade stopped at the Shipki La pass? What is the cultural and spiritual connection that binds people on both sides of the border? Did the Shipki La pass account for a great volume of bilateral trade between India and China? Will its reopening encourage religious tourism?

EXPLAINER

Tikender Singh Panwar

The story so far:
Himachal Pradesh has opened the Shipki La pass, a motorable mountain pass in the Kinnaur district, to domestic tourists, a step which locals hope will revitalise tourism and trade.

What is its historical importance?
Centuries before national borders and geopolitical tensions defined regions, the Shipki La Pass in Himachal Pradesh's Kinnaur district served as a vital trade route between India and Tibet (now part of China). Situated at an elevation of 3,930 metres above sea level, the pass has been part of documented trade since the 15th century, although oral histories suggest its legacy extends even further back. According to folklore, cross-border trade was based on an oath sworn by communities on both sides – "Till the water in Kailash Man Sarovar Lake does not dry, a black crow does not turn white, and the highest peak Rijo Pugal does not flatten, this trade agreement shall continue." This poetic pledge symbolised an enduring bond that withstood centuries, until political realities disrupted it.

Why was the trade route closed?
The once-thriving commerce through Shipki La came to a standstill due to a series of geopolitical events. It was first disrupted after the Sino-India War of 1962, followed by further breakdowns post the Doklam standoff and the COVID-19 pandemic. The trade route remains shut to commercial exchange.

Why has the recent intervention sparked enthusiasm?
The Chief Minister of Himachal Pradesh inaugurated tourism access to Shipki La without the previously mandatory permit system. Indian tourists can now visit using just their Aadhaar card, a move that has stirred optimism across the region.

New beginnings: Himachal Pradesh Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu takes part in a performance during the launch of tourism activities, at Shipki La pass in Kinnaur, Himachal Pradesh, on June 10.PTI

The communities of Kinnaur, particularly those from Scheduled Tribes and Scheduled Castes, share a deep-rooted cultural and economic relationship with Tibetan counterparts. Historically, the Bushahr State (now Rampur) in India and Guge in Tibet were principal players in the region's trade. The Kinnaur Indo-China Trade Association, based in Reckong Peo, has voiced a formal appeal to reopen the trade route through Shipki La. The Chief Minister has assured that the issue will be taken up with the Ministry of External Affairs.

What goods were traded?
The commodities exchanged between India and Tibet through Shipki La were both diverse and valuable.

Imports from Tibet included wool (the most profitable item), pack and saddle horses, goats, sheep, mutton, yak and goatskins, yak hair (used for ropes and saddlebags), devotional items such as prayer wheels, thangkas, rosaries, and bowls, as well as borax, turquoise, and gold. Exports to Tibet from India included grains such as barley, wheat, rice, millet, lentils, chickpeas, and oil, dried fruits, vegetables, spices, tobacco, timber, copper and brass utensils, and iron tools.

Gold and turquoise were particularly cherished, which were integral to traditional Kinnauri women's jewellery – creating constant local demand and sustaining artisan communities. These exchanges weren't just transactional; they shaped cultural practices, local crafts, and even dietary habits across generations.

If trade volume is limited, why is there still so much excitement?
It's true that trade through the three land passes with China – including those in Arunachal Pradesh and Uttarakhand – does not account for a significant volume of bilateral trade.

But enthusiasm for trade and tourism lie in connectivity and opportunity. Reopening Shipki La could shorten the journey from Delhi to Mansarovar by 14 days, a potential game-changer for religious tourism and cross-border travel. This could also boost employment for local youth, enhance regional trade infrastructure, and catalyse growth in hospitality and allied sectors.

Additionally, the reopening may serve a strategic purpose as well – a soft diplomatic gesture and a community-led model of cross-border trust-building, independent of high-level state diplomacy. For a region often sidelined in national dialogues, such grassroots engagement could play a crucial role in shaping future peace corridors.

What is the cultural connection?
Unlike the India-Pakistan border, where cross-border blood relations exist, the India-China border around Shipki La is defined more by shared lifestyles than lineage. The people on both sides are primarily pastoralists, and many surnames overlap – for instance, the Namgyal surname is found both in Leh and across the Tibetan plateau.

Cultural ties also endure through religion. Upper Kinnaur and the adjacent Tibetan region predominantly follow Buddhism, sustaining a spiritual and civilisational continuity even in the face of political divisions. Monastic traditions, festivals, and oral lore reflect a shared heritage that survives despite barriers of nationhood. Reopening Shipki La could become more than a regional story – it might just be a case study in diplomacy through development and heritage.

Tikender Singh Panwar is former deputy mayor of Shimla, and member of the Kerala Urban Commission.

THE GIST

- Centuries before national borders and geopolitical tensions defined regions, the Shipki La Pass in Himachal Pradesh's Kinnaur district served as a vital trade route between India and Tibet (now part of China).
- The commodities exchanged between India and Tibet through Shipki La were both diverse and valuable.
- Reopening Shipki La could shorten the journey from Delhi to Mansarovar by 14 days, a potential game-changer for religious tourism and cross-border travel.

शिपकी ला का ऐतिहासिक महत्व

- **प्राचीन व्यापार मार्ग**: शिपकी ला कम से कम 15वीं सदी से एक प्रमुख ट्रांस-हिमालयन व्यापार मार्ग रहा है, जो बुशहर राज्य (भारत) को गुगे (तिब्बत) से जोड़ता था।
- **प्रतीकात्मक व्यापार समझौता**: मौखिक परंपराओं में एक पवित्र व्यापार समझौते का उल्लेख मिलता है, जो **सीमापार विश्वास और सांस्कृतिक निकटता** का प्रतीक है।

- यह मार्ग केवल आर्थिक नहीं बल्कि **सभ्यतागत संबंधों** का माध्यम था, जिसने सदियों तक जीविका, रीति-रिवाजों और धार्मिक परंपराओं को आकार दिया।

व्यापार क्यों बंद हुआ?

- शिपकी ला के माध्यम से व्यापार बंद होने के प्रमुख कारण:
  - 1962 का **भारत-चीन युद्ध**
  - **डोकलाम विवाद** और बढ़ता भू-राजनीतिक अविश्वास
  - **कोविड-19 महामारी**
- उत्तराखंड (लिपुलेख) और अरुणाचल प्रदेश (नाथु ला) जैसे दर्रों की तरह शिपकी ला से भी **चीन के साथ औपचारिक व्यापार** अब तक बंद है।

वर्तमान विकास: घरेलू पर्यटन की शुरुआत

- **हिमाचल प्रदेश सरकार ने परमिट प्रणाली समाप्त कर दी है**, और अब भारतीय पर्यटक केवल **आधार कार्ड के साथ** शिपकी ला जा सकते हैं।
- **स्थानीय इंडो-चाइना ट्रेड एसोसिएशन** ने केंद्र सरकार से व्यापार पुनः खोलने की औपचारिक मांग की है।
- **मुख्यमंत्री ने विदेश मंत्रालय के समक्ष यह मुद्दा उठाने की प्रतिबद्धता** व्यक्त की है।

सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंध

- यह क्षेत्र तिब्बत के साथ **तिब्बती-बौद्ध विरासत** साझा करता है, जिसमें मठवासी परंपराएं, त्यौहार और समान उपनाम शामिल हैं।
- मार्ग को फिर से खोलने से **कैलाश-मानसरोवर तीर्थ यात्रा** को समर्थन मिल सकता है, जिससे यात्रा **14 दिन तक कम** हो सकती है।
- यह दर्रा **राजनीतिक सीमा से अधिक एक साझी पशुपालक और आध्यात्मिक जीवनशैली** का प्रतीक है।

आर्थिक और रणनीतिक निहितार्थ

- **व्यापारिक मात्रा**: भले ही यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान न देता हो, लेकिन यह **स्थानीय कारीगरों और समुदायों के लिए जीवनरेखा** है।
- प्रमुख वस्तुएं:
  - **तिब्बत से**: ऊन, याक, धार्मिक सामग्री, सोना
  - **भारत से**: अनाज, औज़ार, मसाले, तांबा
- **पर्यटन क्षमता**: इससे **हॉस्पिटैलिटी, अवसंरचना** और **स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार** के अवसर बढ़ सकते हैं।

- **रणनीतिक सॉफ्ट डिप्लोमेसी**: यह पहल **सामुदायिक नेतृत्व वाले विश्वास निर्माण** को बढ़ावा देती है — एक **"शांति गलियारा" मॉडल**।

निष्कर्ष:

शिपकी ला को पर्यटन के लिए खोलना भू-राजनीतिक दृष्टिकोण से भले ही छोटा कदम लगे, लेकिन यह **सांस्कृतिक, आर्थिक और कूटनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण** है। यह **नीचे से ऊपर की ओर कूटनीति** (Bottom-up Diplomacy) का एक मॉडल प्रस्तुत करता है, जहाँ **स्थानीय पहचान, विरासत और आजीविका** संघर्ष के बजाय **संपर्क की कहानी** को आकार देते हैं। दीर्घकाल में, इस प्रकार के कदम **भारत-चीन जैसे संवेदनशील सीमाओं** पर **विश्वास निर्माण उपायों (CBMs)** में एक निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।

UPSC Mains Practice Question

Ques: शिपकी ला दर्रे को फिर से खोलना व्यापार से परे भी महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक कूटनीति, क्षेत्रीय विकास और भारत-चीन संबंधों के लिए इसके निहितार्थों पर चर्चा करें। (**250 words)**

Page : 11 : GS 3 : Science and Technology

भारत का "न्यूस्लियर क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम (CLNDA), 2010" परमाणु दुर्घटनाओं के पीड़ितों को त्वरित मुआवजा सुनिश्चित करने और स्पष्ट दायित्व मानदंड स्थापित करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। हालांकि, इस कानून के विशिष्ट आपूर्तिकर्ता दायित्व प्रावधान — विशेष रूप से **धारा 17(b) और 46** — विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश से रोकते रहे हैं, जिससे जैतापुर और कोव्वाडा जैसी रणनीतिक परियोजनाओं में देरी हुई है। सरकार द्वारा इन प्रावधानों में ढील देने की संभावित पहल निवेशक विश्वास और सार्वजनिक सुरक्षा व विधायी मंशा के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास है।

What are the ambiguities in India's nuclear liability law?

What are the provisions of the Indian nuclear liability law? What does it say about supplier liability in the event of a nuclear accident? Why do some provisions in the law continue to make foreign companies wary?

Diksha Munjal

The story so far:

As per a Reuters reports, India is reportedly planning to ease its nuclear liability laws, with respect to accident-related fines on equipment suppliers, in order to attract more U.S. firms which have been holding back due to the risk of unlimited exposure.

What is the law governing nuclear liability in India?

Laws on civil nuclear liability ensure that compensation is available to the victims for nuclear damage caused by a nuclear incident or disaster and set out who will be liable for those damages. The international nuclear liability regime consists of multiple treaties and was strengthened after the 1986 Chernobyl nuclear accident. The umbrella Convention on Supplementary Compensation (CSC) was adopted in 1997 with the aim of establishing a minimum national compensation amount. The amount can further be increased through public funds (to be made available by the contracting parties), should the national amount be insufficient to compensate the damage caused by a nuclear incident.

Even though India was a signatory to the CSC, Parliament ratified the convention only in 2016. To keep in line with the international convention, India enacted the Civil Liability for Nuclear Damage Act (CLNDA) in 2010, to put in place a speedy compensation mechanism for victims of a nuclear accident. The CLNDA provides for strict and no-fault liability on the operator of the nuclear plant, where it will be held liable for damage regardless of any fault on its part. It also specifies the amount the operator will have to shell out in case of damage caused by an accident at ₹1,500 crore and requires the operator to cover liability through insurance or other financial security. In case the damage claims exceed ₹1,500 crore, the CLNDA expects the government to step in and has limited the government liability amount to the rupee equivalent of 300 million Special Drawing Rights (SDRs) or about ₹2,100 to ₹2,300 crore. The Act also specifies the limitations on the amount and time when action for compensation can be brought against the operator.

India currently has 22 nuclear reactors with over a dozen more projects planned. All the existing reactors are operated by the state-owned Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL).

What does the CLNDA say on supplier liability?

The international legal framework on civil nuclear liability, including the annex of the CSC is based on the central principle of exclusive liability of the operator of a nuclear installation and no other person. In the initial stages of the nuclear industry's development, foreign governments and the industry agreed that excessive liability claims against suppliers of nuclear equipment would make their business unviable and hinder the growth of nuclear energy, and it became an accepted practice for national laws of countries to channel nuclear liability to the operators of the plant with only some exceptions. Two other points of rationale were also stated while accepting the exclusive operator liability principle – one was to avoid legal complications in establishing separate liability in each case and the second was to make just one entity in the chain, that is the operator to take out insurance, instead of having suppliers, construction contractors and so on take out their own insurance.

Section 10 of the annex of the CSC lays down "only" two conditions under which the national law of a country may provide the operator with the "right of recourse", where they can extract liability from the supplier – one, if it is expressly agreed upon in the contract or two, if the nuclear incident "results from an act or omission done with intent to cause damage".

However, India, going beyond these two conditions, for the first time introduced the concept of supplier liability over and above that of the operator's in its civil nuclear liability law, the CLNDA. The architects of the law recognised that defective parts were partly responsible for historical incidents such as the Bhopal gas tragedy in 1984 and added the clause on supplier liability. So, apart from the contractual right of recourse or when "intent to cause damage" is established, the CLNDA has a Section 17(b) which states that the operator of the nuclear plant, after paying their share of compensation for damage in accordance with the Act, shall have the right of recourse where the "nuclear incident has resulted as a consequence of an act of supplier or his employee, which includes supply of equipment or material with patent or latent defects or sub-standard services".

Why is the supplier liability clause an issue in nuclear deals?

Foreign suppliers of nuclear equipment from countries as well as domestic suppliers have been wary of operationalising nuclear deals with India as it has the only law where suppliers can be asked to pay damages. Concerns about potentially getting exposed to unlimited liability under the CLNDA and ambiguity over how much insurance to set aside in case of damage claims have been sticking points for suppliers.

Suppliers have taken issue with two specific provisions in the law, Section 17(b) and Section 46.

The latter clause goes against the Act's central purpose of serving as a special mechanism enforcing the channelling of liability to the operator to ensure prompt compensation for victims. Section 46 provides that nothing would prevent proceedings other than those which can be brought under the Act, to be brought against the operator. This is not uncommon, as it allows criminal liability to be pursued where applicable. However, in the absence of a comprehensive definition on the types of 'nuclear damage' being notified by the Central Government, Section 46 potentially allows civil liability claims to be brought against the operator and suppliers through other civil laws such as the law of tort. While liability for operators is capped by the CLNDA, this exposes suppliers to unlimited amounts of liability.

What are existing projects in India?

The Jaitapur nuclear project has been stuck for more than a decade – the original MoU was signed in 2009. In 2016, Électricité de France (EDF) and NPCIL signed a revised MoU, and in 2018, the heads of both signed an agreement on the "industrial way forward" in the presence of Indian Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron. In 2020, the EDF submitted its techno-commercial offer for the construction of six nuclear power reactors but an EDF official told that the issue arising from India's nuclear liability law remains an item on the "agenda for both countries". Multiple rounds of talks have not yet led to a convergence on the issue. Other nuclear projects, including the nuclear project proposed in Kovvada, Andhra Pradesh, have also been stalled. Despite signing civil nuclear deals with a number of countries, including the U.S., France and Japan, the only foreign presence in India is that of Russia in Kudankulam – which predates the nuclear liability law.

What is the government's stand?

The central government has maintained that the Indian law is in consonance with the CSC till now. About Section 17(b), it said that the provision "permits" but "does not require" an operator to include in the contract or exercise the right to recourse.

However, legal experts have pointed out that a plain reading of Section 17 of the CLNDA suggests that Section 17(a), (b) and (c) are distinctive and separate, meaning even if the right to recourse against the supplier is not mentioned in the contract [as provided by Section 17 (a)], the other two clauses stand. This effectively means that the supplier can be sued if defective equipment was provided or if it can be established that the damage resulted from an act of intent. Besides, it would not be sound public policy if the NPCIL, a government entity, entered into a contract with a supplier and waived its right to recourse in the contract, despite the fact that the law provides for such recourse. Further, the Ministry of External Affairs had said that Parliament debates over the CLNDA had rejected amendments to include the supplier, and therefore the supplier cannot be liable under this kind of "class-action suit". However, private sector players were not convinced and experts point out that during a trial, what would be considered is what is enshrined in the statute and not what was discussed in Parliament.

This article was first published on April 26, 2023.

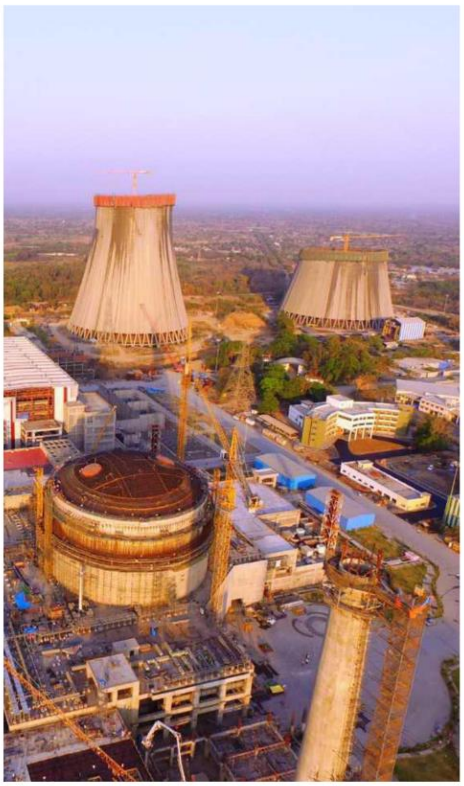

Easing laws: A view of a Pressurised Heavy Water Reactor (PHWR) in Gujarat in 2017. FILE PHOTO

कानून के प्रमुख प्रावधान:

• संचालक की कड़ी दायित्व व्यवस्था:

- संचालक (Operator) बिना दोष सिद्ध किए ₹1,500 करोड़ तक का उत्तरदायी होता है। इसके बाद सरकार 300 मिलियन एसडीआर (~₹2,300 करोड़) तक की जिम्मेदारी ले सकती है।

• प्रतिप्राप्ति का अधिकार (Section 17):

संचालक आपूर्तिकर्ता से क्षतिपूर्ति मांग सकता है यदि:

- अनुबंध में यह अनुमति हो (17a)
- घटना जानबूझकर क्षति पहुँचाने के इरादे से हुई हो (17c)
- आपूर्ति किए गए उपकरण में छिपे या स्पष्ट दोष हों (17b)

• धारा 46:

- यह अन्य नागरिक या आपराधिक दायित्व को सीमित नहीं करती, जिससे CLNDA के बाहर असीमित नागरिक मुकदमों या दावों की संभावना बनती है।

स्पष्टता की कमी और चुनौतियाँ:

• आपूर्तिकर्ता दायित्व (17b):

- भारत एकमात्र देश है जिसने **वैधानिक रूप से आपूर्तिकर्ता दायित्व** लागू किया है, जबकि अंतरराष्ट्रीय मानदंड (CSC) में केवल संचालक ही उत्तरदायी होता है।
- इससे यह अनिश्चितता पैदा होती है कि आपूर्तिकर्ता को कितना बीमा लेना होगा।
- यह वैश्विक कानूनी मानकों से परे हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है।

• नागरिक और आपराधिक जोखिम (46):

- यद्यपि इसका उद्देश्य अतिरिक्त उपाय (जैसे आपराधिक मुकदमा) प्रदान करना है, यह **कानूनी अनिश्चितता** उत्पन्न करता है क्योंकि यह आपूर्तिकर्ताओं को अन्य कानूनों के तहत असीमित दायित्व में डाल सकता है — जिससे निवेश हतोत्साहित होता है।

• सरकारी स्थिति बनाम कानूनी व्याख्या:

- सरकार का कहना है कि प्रतिप्राप्ति का अधिकार "वैकल्पिक" है, अनिवार्य नहीं।
- जबकि कानूनी विशेषज्ञों का मत है कि 17a, 17b, और 17c — सभी उपधाराएं **स्वतंत्र रूप से लागू करने योग्य** हैं, जिससे भ्रम उत्पन्न होता है।

• रणनीतिक परियोजनाओं पर प्रभाव:

- **जैतापुर (फ्रांस की EDF)** और **कोव्वाडा (अमेरिकी भागीदारों)** जैसी परियोजनाओं में समझौता ज्ञापन (MoUs) होने के बावजूद कोई प्रगति नहीं हुई।
- केवल **रूस की कुडनकुलम परियोजना** ही आगे बढ़ सकी है, क्योंकि यह CLNDA से पहले शुरू हुई थी — यह 2010 के बाद निवेशकों की हिचकिचाहट को दर्शाता है।

भारत में आपूर्तिकर्ता दायित्व क्यों लाया गया?

- यह दृष्टिकोण भारत की **औद्योगिक आपदाओं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि**, विशेषकर **1984 की भोपाल गैस त्रासदी** से उत्पन्न हुआ, जहाँ कंपनी की लापरवाही और जवाबदेही के अभाव ने बड़े पैमाने पर जान-माल की हानि की, लेकिन कोई महत्वपूर्ण मुआवजा नहीं मिला।
- **विदेशी कंपनियों की भागीदारी** की स्थिति में जवाबदेही सुनिश्चित करना **नैतिक और संप्रभु दायित्व** माना गया।

प्रस्तावित ढील के निहितार्थ:

• सकारात्मक पहलू:

- यह कदम भारत के परमाणु क्षेत्र में विदेशी निवेश को पुनर्जीवित कर सकता है, जो **स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों** के अनुरूप है।
- **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण** और ऊर्जा स्रोतों के **विविधीकरण** को प्रोत्साहित करेगा।

• चिंताएँ:

- पीड़ितों के लिए मुआवजा प्रणाली के **कमजोर होने का खतरा** हो सकता है।
- यदि संतुलित तरीके से नहीं किया गया तो इसे **जवाबदेही में कमी** के रूप में देखा जा सकता है।
- यदि यह केवल कार्यकारी व्याख्या के माध्यम से किया गया और **कानूनी संशोधन द्वारा समर्थित नहीं हुआ**, तो यह कानूनी चुनौतियों का सामना कर सकता है।

निष्कर्ष:

भारत की **परमाणु दायित्व प्रणाली** पीड़ितों के अधिकारों और सार्वजनिक जवाबदेही पर आधारित रही है। हालांकि, कानून में मौजूद अस्पष्टताएँ — विशेष रूप से **आपूर्तिकर्ता दायित्व और ओवरलैपिंग कानूनी जोखिमों** को लेकर — वैश्विक साझेदारियों में बाधक रही हैं। एक **संतुलित और सूक्ष्म सुधार** जो निवेशकों का विश्वास बढ़ाए और साथ ही **जन सुरक्षा के मूल सिद्धांतों से समझौता न करे**, भारत की **नागरिक परमाणु क्षमता** को **ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु लक्ष्यों** के अनुरूप गति देने में सहायक हो सकता है।

UPSC Mains Practice Question

Ques: भारत का परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010, सार्वजनिक सुरक्षा को अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के साथ संतुलित करने का प्रयास करता है। भारत की परमाणु ऊर्जा नीति के संदर्भ में इसके आपूर्तिकर्ता दायित्व प्रावधानों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा करें। **(250 Words)**

Page : 08 Editorial Analysis

India's uneasy balancing act in the Bay of Bengal

India's economic engagements in the Bay of Bengal appear to be entering a new phase. On the face of it, there is reason for quiet confidence. Trade volumes through India's eastern ports are up. Cargo throughput at Visakhapatnam (Andhra Pradesh), Paradip (Odisha), and Haldia (West Bengal) has grown steadily. The signing of the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) Maritime Transport Cooperation Agreement earlier this year promises to ease regulatory frictions and reduce port costs. For a region long characterised by low trade integration, these are welcome signs.

The decision on Bangladesh

And yet, the optimism sits uneasily alongside a decision that has raised more than a few eyebrows. In early April, India withdrew the transshipment facility it had granted to Bangladesh – an arrangement that had allowed Dhaka to route exports through Indian ports to third-country destinations. The official explanation was logistical: Indian terminals were congested, and delays were hurting exporters. That may well be true. But in Dhaka, the move was read differently – as a quiet assertion of Indian disapproval, possibly linked to Bangladesh's recent diplomatic overtures toward China. The timing was hardly a coincidence. The announcement came after Bangladesh's interim Chief Adviser, in a speech in Beijing, described India's northeastern States as 'landlocked' and cast Bangladesh as the region's maritime lifeline – a claim that did not sit well in New Delhi. Prime Minister Narendra Modi has repeatedly underscored the strategic and economic importance of the Northeast, with Indian Ministers also championing its role in regional connectivity. The suggestion that these States are dependent on Bangladesh for maritime access struck a nerve.

This came as India has doubled down to position itself as a regional integrator. In recent years, New Delhi has invested heavily in port infrastructure through the Sagarmala programme to improve coastal logistics and connectivity. Cargo movement on the east coast has more than doubled in a decade, aided by policy changes such as Goods and Services Tax (GST) cuts on bunker fuel and incentives for coastal shipping. Maritime trade is, by all measures, a national priority.

Abhijit Singh

is the former head of maritime policy at the Observer Research Foundation (ORF), New Delhi

India risks undermining the idea of cooperative regionalism it has sought to promote if it begins using trade access to signal political displeasure

Tensions amid reenergised BIMSTEC

At the regional level, India has sought to reinvigorate BIMSTEC. The BIMSTEC Maritime Transport Cooperation Agreement, for instance, aims to harmonise customs procedures and foster multimodal linkages, with the broader goal of reducing the cost and friction of trade within the Bay. For smaller economies such as Bhutan, Myanmar and Nepal, improved access through Indian ports remains a lifeline.

That is what makes the rollback of Bangladesh's transshipment facility seem somewhat jarring. It reintroduces conditionality into what had been presented as a neutral economic architecture – one where trade facilitation serves regional integration, not shifting political winds. For Bangladesh, the impact is immediate: exporters, particularly in the ready-made garment sector (which accounts for over 85% of the country's foreign earnings), will likely bear the brunt. Many had come to rely on Indian gateways for faster, cheaper access to global markets. The alternatives – via Sri Lanka or Southeast Asia – are costlier and less time-efficient. The move injects uncertainty into Bangladesh's export logistics at a time of already fragile demand.

Tensions have since escalated. In mid-May, India placed restrictions on the import of seven categories of Bangladeshi goods, which include garments, plastics, and processed foods, through land ports in the Northeast. These products can now only enter India through seaports such as Kolkata and Nhava Sheva (Maharashtra), which raises costs and delays. Indian officials cited Dhaka's restriction on yarn imports via land routes as justification, though India's revocation of the transshipment facility had preceded that move. Many in Bangladesh, nonetheless, view New Delhi's response as disproportionate.

Some in Delhi argue that Dhaka is being reminded of the risks of strategic hedging. Bangladesh has, after all, stepped up diplomatic engagement with China, reopened maritime trade with Pakistan, and asserted its role as a regional connector. But these are choices Dhaka is entitled to make. If India recalibrates trade access to signal political displeasure, it risks undermining the very idea of cooperative regionalism it has sought to promote.

This is not just a bilateral issue. What affects Dhaka will be noted in Naypyidaw, Bangkok, and Colombo. The concern is not that India has used leverage – major powers often do. The concern is that India has done so in a domain once insulated from overt geopolitical contest. Maritime trade corridors, once seen as shared infrastructure, are beginning to feel more transactional.

The issue is about credibility

India still holds many cards. Its port infrastructure remains the most extensive and efficient in the region. Cargo-handling capacity is expanding rapidly, and coastal shipping and multimodal linkages are more developed than those of any other BIMSTEC partner. But infrastructure alone does not confer leadership. In a region as fragmented and wary as the Bay, credibility matters as much as capacity. If neighbours begin to view Indian trade facilitation as shifting with the political winds, they will hedge – and the regional architecture India hopes to build will inevitably stall.

The Bay of Bengal, then, is at an inflection point. On one level, it is a zone of opportunity. With improved connectivity, it could emerge as a self-sustaining corridor between South and Southeast Asia. A proposed BIMSTEC free trade agreement, if concluded and implemented well, could reshape regional trade patterns. On another level, the region remains vulnerable to strategic anxieties. The line between economic policy and geopolitical preference is beginning to blur.

There may still be time to draw that line more clearly. India could clarify the circumstances under which the transshipment arrangement with Bangladesh might be reinstated – or, better yet, replace it with a rules-based mechanism that insulates trade from political cycles. That would send a reassuring signal not only to Dhaka but to the rest of the Bay.

The larger question is whether India can maintain the balance between asserting strategic interests and cultivating regional trust. So far, the signals are mixed.

Paper 02 : Internaional Relations

UPSC Mains Practice Question : बंगाल की खाड़ी में भारत की बढ़ती समुद्री उपस्थिति को क्षेत्रीय विश्वास के साथ रणनीतिक हितों को संतुलित करने की आवश्यकता से चुनौती मिल रही है। बांग्लादेश के साथ हाल के घटनाक्रमों के आलोक में क्षेत्रीय संपर्क के लिए भारत के दृष्टिकोण का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। (250 words)

Context :

भारत की बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में भागीदारी अब एक जटिल चरण में प्रवेश कर चुकी है। समुद्री अवसंरचना और BIMSTEC एकीकरण में प्रशंसनीय प्रगति के बावजूद, **भारत द्वारा बांग्लादेश की ट्रांसशिपमेंट सुविधा वापस लेने और कुछ आयातों पर प्रतिबंध लगाने का हालिया निर्णय**, सहकारी क्षेत्रीयतावाद से रणनीतिक हितों की लेन-देन आधारित अभिव्यक्ति की ओर एक बदलाव को दर्शाता है। यह कदम क्षेत्रीय साझेदारों को असहज कर सकता है और **"सौम्य क्षेत्रीय नेतृत्वकर्ता"** के रूप में भारत की विश्वसनीयता को कमजोर कर सकता है।

प्रमुख घटनाक्रम और संदर्भ:

• बांग्लादेश को ट्रांसशिपमेंट सुविधा की वापसी (अप्रैल 2025):

- पहले बांग्लादेश को भारतीय बंदरगाहों के माध्यम से वैश्विक निर्यात की अनुमति थी।
- यह सुविधा "बंदरगाहों पर भीड़" का हवाला देकर रद्द की गई, लेकिन ढाका में इसे **चीन के साथ घनिष्ठ संबंधों और भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों को "लैंडलॉक्ड" कहे जाने** की टिप्पणी पर प्रतिशोध के रूप में देखा जा रहा है।

• बांग्लादेशी वस्तुओं पर आयात प्रतिबंध (मई 2025):

- वस्त्र, प्लास्टिक, और प्रोसेस्ड खाद्य उत्पाद अब केवल **समुद्री मार्गों** से ही भारत में आ सकते हैं, **स्थलमार्ग (उत्तर-पूर्व भारत) से नहीं**।
- वैश्विक मांग में गिरावट के बीच इसे **अत्यधिक और प्रतिशोधात्मक** माना गया है।

• क्षेत्रीय संदर्भ – BIMSTEC का पुनरोत्थान:

- भारत BIMSTEC को मजबूत करने और **नियम-आधारित, एकीकृत क्षेत्रीय आर्थिक ढांचे** को बढ़ावा देने के प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है।
- **BIMSTEC समुद्री परिवहन सहयोग समझौता** और **सागरमाला परियोजना** जैसे प्रयासों से बहु-माध्यमीय संपर्क और तटीय व्यापार को बढ़ावा मिल रहा है।

रणनीतिक और कूटनीतिक तनाव:

• राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है:

- भारत द्वारा दी गई आर्थिक छूटों को वापस लेना, **बांग्लादेश को चीन और पाकिस्तान से दूरी बनाने का संकेत देने** के रणनीतिक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

• व्यापार और रणनीति की सीमाएँ धुंधली हो रही हैं:

- पहले जो **साझा और तटस्थ अवसंरचना** मानी जाती थी, वह अब **राजनीतिक पुनर्मूल्यांकन** का विषय बन रही है — जिससे BIMSTEC के छोटे सदस्य राष्ट्र असहज महसूस कर सकते हैं।

• भारत की विश्वसनीयता दांव पर:

- भारत के पास क्षेत्र में सबसे अच्छा बंदरगाह अवसंरचना है, लेकिन नेतृत्व तभी मान्य होगा जब यह **पूर्वानुमानित और नियम-आधारित व्यवहार** पर आधारित हो — न कि एकतरफा निर्णयों पर।

• क्षेत्रीय विश्वास पर प्रभाव:

- इन कदमों को यदि दबाव की रणनीति के रूप में देखा गया, तो **पड़ोसी देश "हेजिंग रणनीतियाँ" अपनाने लग सकते हैं**, जिससे वही **संपर्क तंत्र कमजोर** हो सकता है जिसे भारत मजबूत करना चाहता है।

भारत की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं पर प्रभाव:

• सकारात्मक प्रगति:

- विशाखापत्तनम, हल्दिया, पारादीप जैसे बंदरगाहों में विस्तार हो रहा है।
- तटीय माल ढुलाई और शिपिंग प्रोत्साहनों से व्यापार वॉल्यूम में वृद्धि हुई है।

• चुनौतियाँ:

- भारत की कार्रवाई से यह धारणा बन रही है कि **प्रवेश की अनुमति राजनीतिक संरेखण पर निर्भर है**।
- यह BIMSTEC के **Free Trade Agreement (FTA)** जैसे एकीकरण फ्रेमवर्क को पटरी से उतार सकता है।

आगे का रास्ता:

• नियम-आधारित पहुंच बहाल करें या उसका विकल्प दें:

- बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट को **स्पष्ट, नियम-आधारित मानदंडों के साथ फिर से खोलना** पूर्वानुमानित और समावेशी कूटनीति की ओर वापसी का संकेत होगा।

• रणनीतिक मतभेदों को व्यापार से अलग रखें:

- **आर्थिक संपर्क को दबाव की रणनीति के रूप में उपयोग करने से बचें**, विशेष रूप से उन क्षेत्रीय समूहों में जहाँ **सहयोग और आम सहमति** ही मुख्य स्तंभ हैं।

• क्षेत्रीय संवाद मंचों को मजबूत करें:

- BIMSTEC के भीतर **विश्वास निर्माण तंत्रों** का विस्तार करें ताकि **उभरते तनावों को आर्थिक नुकसान के बिना** सुलझाया जा सके।

निष्कर्ष:

बंगाल की खाड़ी में भारत का समुद्री और क्षेत्रीय नेतृत्व केवल अवसंरचना और व्यापार पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें पूर्वानुमानिता, समावेशन और विश्वास की भावना भी होनी चाहिए। आर्थिक पहुंच को रणनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करना **अल्पकालिक लाभ** तो दे सकता है, लेकिन इससे वही **क्षेत्रीय ढांचा दीर्घकाल में बिखर सकता है** जिसे भारत बनाना चाहता है। यदि भारत को **एक शक्तिशाली पड़ोसी से आगे बढ़कर एक जिम्मेदार क्षेत्रीय स्तंभ** के रूप में देखा जाना है, तो उसे **आक्रामकता और समावेशिता के बीच संतुलन** बनाए रखना होगा।